

Jansatta, Delhi

Tuesday 27th January 2015, Page: 1

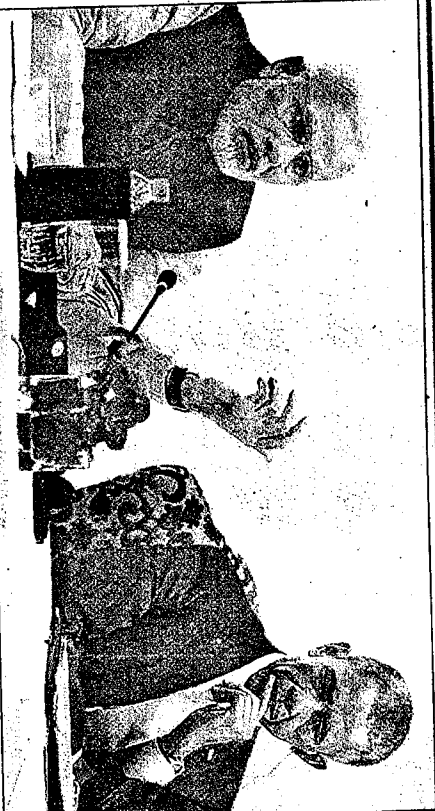
Width: 22.43 cms, Height: 15.76 cms, 44r, Ref: pmin.2015-01-27.19.7

तरक्की के लिए निवेश को बढ़ावा देगा भारत कई क्षेत्रों में मिल कर काम करेंगे, ओबामा ने भी दिया भरोसा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 26 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका व्यावसायिक सम्मेलन में कहा कि हमने आर्थिक वृद्धि बढ़ाने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए पिछले आठ महीने में अथक प्रयास किए हैं। सरकार निवेश को बढ़ावा देने वाला और उद्यमों को प्रोत्साहित करने वाला माहौल देगी। मोदी ने कहा कि वे खुद व्यक्तिगत रूप से बड़ी परियोजनाओं पर नजर रखेंगे। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बौद्धिक संपदा अधिकार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हमें अभी काफी क्षेत्रों में साथ काम करने की जरूरत है।

नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के दिग्गज उद्योगियों को संबोधित करते हुए कहा- मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ी परियोजनाओं पर नजर रखूंगा। उन्होंने कहा कि बड़ी परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी के सुझाव से सहमत हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा- 'एक अच्छा सुझाव आया है कि बड़ी परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर नजर रखी जाए। मैं इस सुझाव से सहमत हूँ, मैं बड़ी परियोजनाओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उन पर खुद नजर रखूंगा।' भरोसेमंद कर व्यवस्था को वाला करते हुए मोदी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के लिए नीतियों में निरंतरता जरूरी है। भारत में हर क्षेत्र में भारी संभावनाएं हैं। लोगों की कय शक्ति बढ़ाने के लिए अव्यवस्था में वृद्धि जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संभावनाओं से परिपूर्ण है।



दिल्ली में सोमवार को भारत-अमेरिकी सीईओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा।

हमारे पास प्रतिभा और अवसर हैं। हम कौशल, आकार और गति पर ध्यान देना चाहते हैं। शक्ति के लिए समृद्ध कोई गारंटी नहीं है। भारत दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है। व्यवसाय करने के लिहाज से बेहतर शीर्ष 50 देशों में जाह्न बनाने का हमारा लक्ष्य है। फोरम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि दोनों देशों को जिन खास चीजों पर काम करने की जरूरत है उनमें दोनों देशों में कारोबार करना आसान बनाना शामिल है। उन्होंने कहा- अब भी

कई बाधाएं हैं।' इसलिए नियमनों को तुरन्त करने, लातफ्रीताशाही हटाने और नौकरशाही से परे जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत में चार अरब डॉलर निवेश की घोषणा की जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मदद के लिए अमेरिका की ओर से निर्यात के वित्त पोषण के लिए एक अरब डॉलर, लघु व मध्यम उद्यमों के लिए एक अरब डॉलर और अथवा कर्जा परियोजनाओं में दो अरब डॉलर का निवेश शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी निर्यातक भारत में

बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर बहुत चिंतित है क्योंकि अमेरिकी अव्यवस्था नेजी से ज्ञान आधारित अव्यवस्था का रूप ले रही है। ओबामा ने कहा कि भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण की कारगर व्यवस्था के अभाव में कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम वैश्विक मूल्यवर्धन प्रवृत्ति के उच्चतम स्तर पर काम करना चाहते हैं। निवेश लाने के लिए मोदी की सुधार संबंधी पहल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा- हमें व्यापार को दबाने वाली योजना के बजाय

- मोदी के वादे**
- बड़ी परियोजनाओं की निगरानी खुद करेंगे
 - कर व्यवस्था को भरोसेमंद और आसान बनाएंगे
 - कारोबार के लिए दुनिया के 50 देशों में जाह्न बनाने का लक्ष्य
- ओबामा ने कहा**
- अमेरिकी निवेशकों के लिए 'लातफ्रीताशाही' खत्म करे भारत
 - बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मुद्दों का समाधान हो
 - भारत का नक्शा बदलने के लिए मोदी ने भरा जोश

तरक्की के लिए निवेश को बढ़ावा देगा भारत

पेज 1 का बाकी

के बजाय इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें पारदर्शी, सुसंगत होने और बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत है।'

भारत व अमेरिका के दिग्गज उद्यमियों की यहां हुई बैठक में अमेरिकी प्रतिबंधों को तीसरे देश की कंपनी पर लागू करने, कारोबारी माहौल आसान बनाने और बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण जैसे दर्जनों विषयों से जुड़े मुद्दे उठाए गए। भारत-अमेरिका सीईओ फोरम की इस बैठक में भारत के उद्योगपतियों ने दोनों देशों से जुड़े मुद्दों को आपस में साझा किया और सभी मुद्दों को उठाने के बजाए केवल प्रासंगिक क्षेत्रों की बात की।

इस बैठक में बाद में ओबामा व मोदी ने अपनी बात रखी। इसमें भारतीय सीईओ को केवल 18 मिनट का समय दिया गया था। चर्चा को देखने वाले सूत्रों ने बताया कि पांच सीईओ केवल दो-दो मिनट बोले। उसके बाद खुली परिचर्चा हुई जिसमें अन्य सीईओ को अपनी राय रखने का मौका मिला।

एचडीएफसी के दीपक पारेख ने कारोबार करने में द्विपक्षीय सुगमता की बात की तो भारती एंटरप्राइजेज के सुनील मित्तल ने इलेक्ट्रॉनिक संकुल विकास और

स्मार्ट शहर पर विचार रखे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कृषि, नवोन्मेष व कौशल विकास, बायोकान की चेयरमैन किरण मजूमदार शां ने दवा उद्योग व बौद्धिक संपदा (आईपी) से जुड़े मुद्दों को उठाया।

• तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक दिनेश के सराफ ने भारत-अमेरिका के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं होने का जिक्र किया और कहा कि इससे एलएनजी का आयात प्रभावित हो रहा है। मालूम हो कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से प्रतिस्पर्धी कीमत पर प्राकृतिक गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति का आश्वासन चाहता है, लेकिन अमेरिका उन देशों को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति नहीं करता जिनके साथ उसका एफटीए नहीं है। सराफ ने रूस व ईरान जैसे देशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध का मुद्दा भी उठाया।

सूत्रों के अनुसार खुली परिचर्चा में कुमार मंगलम बिड़ला ने अमेरिका में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों के समक्ष चुनौतियों को उठाया। महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद

महिंद्रा ने रक्षा व एकल खिड़की मंजूरी का मुद्दा सामने रखा। आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर ने अमेरिकी कर अपवचना कानून व विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (एफएटीसीए) के प्रावधानों सहित बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे उठाए।

रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग की बात की, तो एस्सार के शशि रूइया ने अमेरिका में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) संबंधी पहल पर विचार रखे।

इस बैठक की सह अध्यक्षता टाटा संस के साइरस मिस्त्री व हनीवेल के डेविड एम कोटे ने की। इसमें भारत व अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। फोरम में 17 सदस्यीय भारतीय दल में अडाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडाणी, टोरेट फार्मा के सुधीर मेहता, एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, भेल के प्रमुख बी प्रसाद राव शामिल हैं। अमेरिकी टीम में पेप्सीको की इंद्रा न्यूी, मैकग्रा हिल फिनांशल के चेयरमैन हेराल्ड मैकग्रा व मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बंगा शामिल थे।

Contd.